

The question was put and the motion was adopted

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY Sir, I move —

‘That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to’

The question was put and the motion was adopted

MOTION RE: THIRTEENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
F H MOHSIN) Sir I beg to move —

“That the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from 1st July 1970 to 30th June 1971, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 23rd August 1973, be taken into consideration”

Sir, we are going to discuss the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. It is unfortunate that the author of this Report, Shrimati Debaki Gopidas, the former Commissioner for Linguistic Minorities, is no more. She died in the air crash near Delhi on the 31st May 1973 while returning from Madras. It is unfortunate that her advice, during the course of the debate on this Report, is denied to us.

Sir, as the House is aware, in accordance with article 350B of the Constitution, the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in July, 1957. The main functions of the Commissioner are to investigate, in accordance with the provisions of article 350B(2), all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities and to report to the President on these matters at such intervals as the President may direct. The Commissioner is expected to send the

Report to the President as and when required by him. But, Sir, now Annual Reports are being prepared by the Commissioner for Linguistic Minorities and are discussed in this House often. Now we are considering the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities.

Sir, the Commissioner has made some remarks in the Report on the safeguards, on the working of the safeguards, for the linguistic minorities.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव उपसभाध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ़ खाली कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर न तो कोई कैबिनेट मन्तर का मंत्री है न लीडर आफ द हाउस है, न व्हिप है कांग्रेस वैन्यू बिलकुल इन्क है। क्या हाउस का चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बिलकुल नहीं है ?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) You are raising the question of quorum only? The concerned Minister is here

SHRI PITAMBER DAS They are caught on the wrong foot

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव कोरम भी नहीं है, सरकार का भी कोई नहीं है। कन्सर्ड मिनिस्टर से ही सबध नहीं है . .

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) सब तो यहाँ मौजूद हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव न व्हिप है, न लीडर आफ द हाउस है कोई मेम्बर भी रूलिंग पार्टी का उपस्थित नहीं है। कोरम का ही सवाल नहीं है। कोरम भी नहीं है, डिक्कोरम भी नहीं है।

श्री ओम् मेहता मैं आ गया हूँ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? आपके हाउस के सदस्य कहाँ हैं ?

श्री श्रीम् मेहता : देखिए, आपको इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। सब आ जायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You can go on, Mr. Mohsin. We are ringing the quorum bell.

SHRI F. H. MOHSIN: Yes, Sir. I was mentioning that the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities is being considered. Sir, as is usual, he prepares the Annual Reports.

(Quorum bell rings)

SHRI K. CHANDRASHEKHARAN: Sir, Opposition Members have to respond to the quorum bell.

THE VICE-CHAIRMAN: Everybody has got the responsibility, you see.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सबसे बड़ी चीज राज्य सभा की प्रतिष्ठा का है, क्योंकि यहां पर इस समय न चीफ व्हिप है, न मंत्रीगण हैं और न ही यहां पर कोरम है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यहां पर कोरम बनाये और जब सरकारी पक्ष के ही लोग गायब हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। आप मिनिस्टर, लीडर और व्हिप से कहिये कि वे सदन में उपस्थित रहें।

श्री राम निवास मिर्धा : आपने कह दिया है तो बहुत काफी है।

श्री पीताम्बर दास : सवाल अहसास का है। अगर अहसास है तो ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes, the Minister.

SHRI F. H. MOHSIN: I was saying that the Commissioner for Linguistic Minorities prepares annual reports, furnishing information about the extent to which constitutional safeguards have been complied with by the State Governments and then implemented by the various State Governments also. The Commissioner also receives complaints from various linguistic minorities and takes up the matter with the State Governments concerned to meet their grievances. The Commissioner as such is now a very important link between the States and the Centre and also in meeting the grievances of the linguistic minorities in every State.

Sir, before the reorganization of States on linguistic basis, many of the States were bilingual or even trilingual. But even after the formation of the States on linguistic basis, the problems of the linguistic minorities still remain, and in some of the States, really important complaints are received very often. They are taken up by the Commissioner for Linguistic Minorities, and after the report is presented the Central Government also takes up those grievances with the State Governments concerned. The safeguards are provided in the Constitution, but often at the meetings of the Chief Ministers and the Education Ministers of all the States concerned, the problems of linguistic minorities are discussed and the decisions arrived at also got implemented by the State Governments. And I am happy to say that co-operation of the State Governments is somewhat encouraging.

Up till now, 12 reports have been laid and discussed here. Now I shall be very happy to hear the observations of the hon. Members of this House on this thirteenth Report. Before saying much about this Report and its implementation, I would be very happy to hear the Members' remarks on this Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): There is one amendment by Mr. Jagdambi Prasad Yadav. Are you moving, Mr. Yadav?

SHRI J. P. YADAV (Bihar): Yes, Sir I beg to move:—

“That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

“and having considered the same, this House is of the opinion that the definition of ‘Linguistic Minorities’ on which the Report is based should be changed so that the facts and figures contained in the Report do not depict a misleading picture.”

The questions were proposed.

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी ताकि प्रान्तों के एक भाषाई राज्य बनाए जा सके और वे राज्य बने। राज्य बनने के पश्चात् राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न भाषा-भाषी लोग हैं, इसलिये प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक भाषा-भाषी लोगों की भाषाओं की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। भाषा-जात और अल्पसंख्यक लोगों की संख्या प्रत्येक प्रान्त में है और इसीलिये उनकी भाषा, संस्कृति की रक्षा के लिये एक भाषा-जात आयुक्त नियुक्त किया गया, ताकि प्रत्येक प्रान्त में अल्पसंख्यकों की भाषा की सुरक्षा की जा सके। उसके पश्चात् यह प्रत्यन चला और प्रत्येक प्रान्त ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया। इस दिशा में हमारी केन्द्रीय सरकार भी थोड़ी सी जागरूक हुई और उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा की सुरक्षा के लिये बहुत तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री महावीर त्यागी : इलेक्शन के वास्ते।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : सरकार का उद्देश्य तो यही है। अगर चुनाव न होते और ईमानदारी के साथ सभी प्रान्तों में इस प्रकार से अपनी बेवैनी प्रकट करती, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वह तो चुनाव की वजह से वहाँ पर ज्यादा सक्रिय हो गई है। परंतु मैं एक बात जानता हूँ,

क्योंकि मैंने इसी सदन में पिछले वर्ष 12वीं रिपोर्ट पर बोलते हुए पंजाब प्रान्त के बारे में कुछ शिकायतें पेश की थीं। परंतु अभी तक वहाँ के भाषा-जात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये इस आयुक्त ने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ थोड़े से आकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। अनुच्छेद 350 (क) और (ख) के अनुसार पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये वहाँ की सरकार ने क्या किया है, व मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब सरकार ने यह बात मानने से ही इनकार कर दिया है कि पंजाब प्रान्त में कोई भाषा-जात अल्पसंख्यक भी है। मैं आयुक्त के शब्दों में ही आपको यह तथ्य बता देना चाहता हूँ—जो कि रिपोर्ट में इस प्रकार दिया गया है—“पंजाब सरकार ने भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में सूचना नहीं दी जो कि सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई प्रश्नावली में मांगी गई थी। पंजाब सरकार का दृष्टिकोण यह है कि प्रश्नावली में सुरक्षाओं को लागू करने के बारे में मांगी गई सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि राज्य में कोई भाषा-जात अल्पसंख्यक है ही नहीं।” यानी पंजाब सरकार इस बात को मानने से इनकार करती है कि पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यक हैं भी। मेरे सामने 61 और 71 के सेन्सस की रिपोर्ट है। उसमें से मैं पंजाब के फिगर्स देना चाहता हूँ। सन '61 में वहाँ पर हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या 1,12,98,855 थी और '71 में 27,05,931 थी जबकि पंजाबी भाषियों की संख्या '61 में 83,43,264 थी और '71 में 1 करोड़ से कुछ ऊपर थी। इस हिसाब से प्रतिशत लगाया जाय तो 25 प्रतिशत का अनुपात वहाँ हिन्दी भाषा-भाषियों का है। साथ ही उर्दू भाषा-भाषी भी हैं। '61 के सेन्सस में वे 2 लाख 55 हजार थे और '71 के सेन्सस में 29 हजार दिखाए गए हैं। इस सब में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब '71 की जनगणना हुई तो उस समय विशेष रूप से पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों को जनगणना की रिपोर्ट लेने के लिये लगाया, जिन्होंने जबरदस्ती लोगों की भाषा पंजाबी लिखी। इतना अन्याय हुआ कि जब हिन्दी भाषा-भाषी 1 करोड़ से 27 लाख रह गए फिर भी

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

वहा हिन्दी भाषा-भाषी 25 प्रतिशत हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पंजाब में जो भाषा जात अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिये आयुक्त ने क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब सरकार ने वहाँ के भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये जो नीति अपनाई है, वह उसी के शब्दों में बताना चाहता हूँ। शिक्षा के संबंध में जो सुरक्षा दी गई है, अल्पसंख्यकों के लिये वह यह "यदि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में 40 छात्र या किसी कक्षा में 10 छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों, तो न्यूनतम एक अध्यापक नियुक्त करके अध्यापन की व्यवस्था करना"। इस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिये, परंतु भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये जो स्थिति पंजाब में है, वह यह है।

'552--पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने जो बैठक में उपस्थित थे कहा कि सरकारी निर्णय के अनुसार सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती, किन्तु हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों को सहाय्यतार्थ अनुदान दिये जाते हैं'

ऐसा पंजाब सरकार ने कहा है "राज्य सरकार से पिछले 5 वर्षों में हिन्दी माध्यम वाले प्राइमरी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहाय्यतार्थ अनुदान के वर्षवार आकड़े देने के लिये कहा गया।" तो वह आकड़े अभी तक नहीं दिये गए। वहाँ के भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लोगों ने शिकायत करते हुए सहायक आयुक्त को अपनी जो शिकायतें उपस्थित की हैं, उसमें उन्होंने यह चीज उपस्थित की है--

"पंजाब सरकार द्वारा सच्चर फारमूले के रद्द किये जाने के बारे में जिसका उल्लेख 12वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 255 में किया गया है, मर्वंदलीय हिन्दी रक्षा समिति ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 350ख और 350क के अधीन की गई व्यवस्था के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पंजाब सरकार को निदेश दिया जाए ताकि भाषा-जात

अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के अधिकार का उस सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाए।"

और, उपाध्यक्ष महोदय, 'भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने महायक आयुक्त के सामने जिनसे वह 1971 में चंडीगढ़ के दौरे के दौरान मिले थे, बताया कि पंजाब के पुनर्गठन के पूर्व अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सरकारी स्कूलों में प्राप्त थी। किन्तु पुनर्गठन के बाद हिन्दी तथा उर्दू भाषियों को प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं है। कहा गया है कि जनगणना के आकड़ों में यह स्पष्ट है कि पंजाब की जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग हिन्दी भाषा-भाषी है, फिर भी पंजाब सरकार संरक्षणों की स्वीकृत योजना के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने पर सहमत नहीं हुई।'

सरकारी प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी भाषा-भाषियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि, उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ प्राइवेट स्कूल हैं जो कि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जब वह विश्वविद्यालय में यहाँ कालेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको हिन्दी भाषा के माध्यम पढ़ने का सुअवसर प्रदान नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति भाषा की है। पंजाब में चाहे वहाँ के उर्दू के भाषाजात अल्पसंख्यक हैं चाहे हिन्दी के हैं, हिन्दी भाषा-भाषी हैं, उनको पंजाब सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही और उनकी मान्यता यह है कि पंजाब एक भाषा-भाषी है, वहाँ अल्पसंख्यक हैं ही नहीं। इस प्रकार की उनकी मान्यता है।

जहाँ तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में जो संरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें संरक्षण इस प्रकार दिया गया है--

“राज्य सेवाओं में भर्ती के राज्य की सरकारी भाषा के पूर्व ज्ञान की शर्त नहीं होनी चाहिये और परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये। राज्य सरकारी भाषा में दक्षता की परीक्षा परीक्षा की अवधि में ली जानी चाहिए।”

परन्तु उपसभापति महोदय, पंजाब प्रान्त में अनिवार्य है कि किसी भी राज्य सेवाओं के लिए कोई भी प्रत्याशी जाता है तो उसके लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य की दृष्टि है, जब कि भाषा-जात अल्पसंख्यकों को इस बात के लिए छूट दी गई है। पंजाब में कोई छूट नहीं है।

जहां तक सरकारी कामकाज में हिन्दी की सुरक्षा का प्रश्न है, उसके लिए इस प्रकार की सुरक्षा आपके यहां दी गई है :—

‘जिला स्तर पर, उसके नीचे नगरपालिका और तहसील आदि के स्तर पर जहां कि भाषा-जात अल्पसंख्यक कुल सख्या के 15—20 प्रतिशत है, प्रमुख सरकारी नोटिस, नियम तथा अन्य प्रकाशन अल्पसंख्यकों की भाषा में निकाले जाने चाहिये।’

यह संरक्षण दिया हुआ है, परन्तु पंजाब की स्थिति क्या है? जो आयुक्त की रिपोर्ट है उसी से आपको यह चीज बनाना चाहता हूं कि वहां कितना संरक्षण प्राप्त है। आयुक्त की रिपोर्ट की धारा 461 में लिखा है :—

“भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने जो मार्च, 1971 चंडीगढ़ में महायुक्त से मिले थे इस बात की शिकायत की कि महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस, नियम आदि अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं और इससे हिन्दी और उर्दू बोलने वालों को कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हिन्दी की नाम पट्टिकाएं और साइन बोर्ड हटा दिये गए थे। किन्तु उन्होंने बताया कि मतदान सूचियां हिन्दी में भी प्रकाशित की गई हैं। भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की ओर पंजाब सरकार का ध्यान आक-

षित किया गया है और उनके विचार होने की प्रतीक्षा है।”

इसके अलावा 462 धारा में आयुक्त रिपोर्ट यह बतलाती है :—

“एक शिकायत इस बारे में भी मिली कि यद्यपि राज्य स्तर तक सारे सरकारी कार्य जनता से पंजाबी या हिन्दी में प्राप्त या के उत्तर याचिकाओं की भाषा में देने में विद्यमान है फिर भी आवेदन पत्र केवल में ही प्राप्त किये जाते हैं और उत्तर उसी भाषा में दिए जाते हैं।”

संरक्षण इस बात का है कि जिस में वहां आवेदन पत्र दिये जायें, उन्हें उत्तर दिया जाय, परन्तु पंजाब में भाषा में केवल आवेदन पत्र दे सकते हैं और भाषा में ही उत्तर दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता वह यह है ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHE RAJU): Tyagji, you are taking y in quotations.

श्री ओडम् प्रकाश त्यागी : पंजाब की नीति यहां तक कड़ी है कि मैं एसा उदाहरण देना चाहता हूं। पंजाब तालों में जहां आंध्र के रोगी जाते आंध्र के रोगों के डाक्टर परीक्षा चार्ट लगा रखते हैं। इसमें कोई का सवाल नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने वालों का चार्ट दिया जाना चाहिये, हिन्दी को हिन्दी का चार्ट दिया जाना पंजाबी पढ़ने वालों को पंजाबी का जाना चाहिये; क्योंकि वे पढ़ सकते हैं। चल सकता है कि उनकी आई साइड में कितनी वीक है। आप आश्चर्य करेंगे के अस्पतालों में पंजाबी भाषा के दिये गये हैं और हिन्दी भाषा के सब चार्ट दिये गये हैं।

श्री महावीर त्यागी : यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : आयुक्त की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : ठीक है, अब आप का टाइम हो गया है ।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : “एक शिकायत इस बारे में प्राप्त हुई थी कि राज्य सरकार ने पंजाब के सभी अस्पतालों में नेत्र परीक्षा के लिए हिन्दी के चार्टों का प्रयोग बन्द कर दिया है । इसके फलस्वरूप केवल हिन्दी जानने वाले रोगियों को बड़ी असुविधा हो रही है और उनके नेत्रों की ठीक-ठीक परीक्षा नहीं हो पाती ।

यह आयुक्त की रिपोर्ट है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : अन्त में मंत्री महोदय से मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भी मैंने शिकायत की थी कि पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । वहाँ आर्य समाज के बहुत कालेज चलते हैं । उन कालेजों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे हिन्दी माध्यम से शिक्षा नहीं दे सकते । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों को यह अधिकार वहाँ पर दिया । पंजाब सरकार यह कहती है कि वहाँ भाषा-जात अल्पसंख्यक हैं ही नहीं । सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है, फिर भी वहाँ के अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आयुक्त जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि भाषा-जात अल्पसंख्यकों का संरक्षण होना चाहिये, उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिये, उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए । और पंजाब में विशेष रूप से मैंने आपके सामने आकड़ें पेश किये हैं । आशा करता हूँ कि आप पंजाब के भाषा-जात अल्पसंख्यकों को दयनीय अवस्था से निकालने की चेष्टा करेंगे ।

SHRI N. R. CHOUDHURY: (Ass: Sir, while going through this Report point that struck my mind was whether are really sincere about solving the problem of the linguistic minorities in the country. According to the Government of India Memorandum of 1956 as also the statement by the Chief Ministers in August 1961, we formulated a national policy till date we have not been able to follow it up and as a result, even after 25 years of independence we have to face linguistic riots in different parts of the country.

Sir, we formulated a policy but there was no such thing as an institution or organisation to supervise or review the different steps taken by the Union territories, State Governments and as a result of this the State Governments, even though their leaders may be sincere, had to succumb to the chauvinistic pressure of reactionary forces of the States. The Chief Ministers' Conference of 1961 felt that zonal councils could serve as the best forum for the purpose of supervision and review. But what happened? After August, 1964, till today the zonal councils never met. Also the Commissioner says in his Report on page 114:—

“Replies from the State/Union territory Governments/Administrations are not received and when they are forthcoming, also they do not always appear to be satisfactory. At the same time the extent to which this office can take up independent investigation to find out the causes of the decreases in the facilities are still limited.”

So, though there are some safeguards in our 1956 Memorandum and also the Chief Ministers' statement, these safeguards are never implemented. As a result even in this year of 1973 when we are discussing this 13th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities, in different parts of our country the problems of linguistic minorities still remain and in certain parts of the country today when we are discussing this Report here in this House, peace is also not there.

Sir, last November when we were discussing the 12th Report I mentioned certain things about Assam. You know, Sir, in this Annexure item No. 10 on page 136—extract from statement issued by meeting of Chief Ministers of States and Central Ministers held in August, 1961—it is mentioned:—

“The question of affiliation of schools and colleges using minority languages to universities and other authorities situated outside the State was considered. It was agreed that in most cases it should be possible to arrange for the affiliation of such institutions to universities or Boards within the State, but where there were insuperable difficulties in making arrangements for such affiliation within the State, they might be affiliated to universities or Boards outside the State.”

This is a clear provision and this provision is there in the Constitution itself also. The linguistic minorities of the State of Assam are demanding that this safeguard should be there and they should not be deprived of the opportunity of having their university education through their mother-tongue. You know hundreds of people gave their lives during last year's language riots. After that a peaceful movement was organised in the District of Cachar and there was an agreement between the then Minister of State for Home Affairs, Mr. K. C. Pant, the Chief Minister of Assam and the Cachar leaders. In that Agreement all the parties agreed that they will give up agitational approach and the matter will be taken up with the university authorities and both the State Government and the Government of India will assist the people of Cachar for attainment of their language rights but, Sir, after that one year has passed and nothing has been done in this matter either by the university or by the State Government or by the Government of India. As a result a separatist movement is now in the offing in that part of the State and I am afraid that unless a tangible workable formula is worked out either by the Government of India or the State Government to solve this problem

of medium of instruction I am the separatist movement will gain and ultimately what will happen cannot say today. Sir, the Bodos were the original settlers of the Assam and they are also demarcated language. They do not support the language policy adopted by the Government of Assam and the university there. I want to say what happens there will be a telegram which I will be justifying. This telegram is addressed to the Minister, the Home Minister and the Members of Parliament. The telegram says:

“Large scale police atrocities against the tribals of Assam going on and arrested in hundreds. Plain Council and Linguistic Minority Committee leaders of Kokrajhar, Prasenjit Brahma and Bhattacharjee arrested under Paddy harvesting badly affected and paralysed.”

This is the telegram. When we are discussing this Thirteenth Report of the Commission for Linguistic Minorities, I also like to draw your attention to other points about Cachar. This was originally a part of the then Bengal. At the time of partition of the country Bengal was partitioned and a part of the then Sube of Bengal went on to Assam. Formerly the Government of India had declared their intention to constitute a Purbachal Pradesh the wards somehow they dropped the name and that part was tagged on to Assam and that is a completely Bengali-speaking geographically separated from the Assam. Now, the Assam Government is trying to impose Assamese in that part of the State as a compulsory language in the secondary stage and also in the Dibrugarh universities, in the universities of the State, they are now moving over to Assamese as the only medium of instruction in the universities. As a result, the demand for Bengali as a medium of instruction rose in that part of the State. There was a peaceful Sa-

[Shri N. R. Choudhury]

movement last year and an agreement was reached between the Central Government and the Assam Government and also the Cachar leaders, but no follow-up action till today has been taken either by the Central Government or by the State Government or by the University. From this attitude we find and also the Report says from 1964 till today the Zonal Council did not meet. Where is the machinery for implementing the national policy on the safeguard of linguistic minorities? There is no such machinery. Once in a year, on the floor of Parliament we all assemble and talk long things. After that we leave, go home and sleep. This way no problem can be solved. The other day we were discussing the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The same thing happens every time in all cases. I think we cannot solve this type of problem. So, it will be my request to the Home Minister that the recommendations of the Commissioner must be made mandatory and there must be an institution for the implementation of the recommendations of the Commissioner for Linguistic Minorities.

Then, Sir, another thing. In this connection one of the most important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education. Unless the Government of India comes forward with financial assistance, the State Government would not be in a position to implement them. Such a view was once expressed by another State Government also. It has been mentioned in this connection that one of the important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education for which it is presumed the State Governments are already subsidised in one form or another. However, the point now made by the State Governments is an indication that a clear direction may be given by the Government of India as to how this problem has to be tackled in future. So, Sir, this responsibility of safeguarding the rights of linguistic minorities must be taken over by the Government of India and for that purpose I think education must be nationalised. Thank you.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): Sir, when the earlier Report of the Commissioner was being discussed in the House last year, some Members pointed out some cases of non-implementation of the recommendations. Today also we find that the same things were repeated by the two previous speakers. It would be better, while replying to this debate the Home Minister is able to tell us what efforts the Government make to get those complaints, which were pointed out last year, removed. Implementation report of those suggestions would be useful.

SHRI K. CHANDRASEKHARA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, this report of the Commissioner for Linguistic Minorities in the country is being discussed every year in Parliament. At the outset I may say that this is one of the most important of reports that this House can possibly discuss because this concerns national integration. Sir, the most important facet of national integration is education, and the purpose of education is the fruit of education has got to be weighed with the results, namely, appointment to some service. Sir, in this country, by and large, recruitment to public service is the only means of getting employment so far as these things are concerned. In several States you have got to depend upon employment under the State Government and therefore, Sir, rightly, this report has tried to project what has been done in the field of education and in the sector of recruitment to public services.

Sir, every year recommendations are made and this year also in this report certain recommendations are made. The recommendations are undoubtedly good far as they go, but we are concerned with the implementation of these recommendations.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

Reading through the last pages of the report, Sir, titled, "The Summary of Implementation of Safeguards" I cannot think that it is more or less a summary of the non-implementation of safeguards.

because what that Chapter has been able to tell us has been more or less what has not been implemented. No doubt there are certain things which have been implemented and we welcome them but in a large sector there is non-implementation. In a large number of States there is non-implementation. May I know from the hon'ble Minister as to what exactly is the machinery for implementation except persuasion? Sir, to a large extent persuasion has got to succeed particularly when matters are taken up in Conferences of Chief Ministers. But I suggest, Sir, that in this field of linguistic minorities there be enacted a Central legislation as also State legislations. By and large, today we proceed on the basis of administrative and executive orders. Sir, I am happy to say it on the floor of this House that even though there are deficiencies and defects, my State of Kerala is one of the States which have sincerely implemented some of these suggested safeguards for the linguistic minorities. That is because a succession of Governments and a succession of sincere, honest officers in charge of the job have thought it fit to see that the implementation of the safeguards is really fulfilment of a national purpose, and that national role will have to be played in that particular State. Sir, even in the State of Kerala there are certain deficiencies which I may point out, so far as one linguistic minority is concerned. That is a deficiency that exists not only in Kerala but also in several other States in the country. I am particularly referring to the claims of the Konkani-speaking population in Kerala and in other States of the country. The Konkani-speaking population is a very energetic force. Wherever they have gone, they have been able to capture the business fields and in the fields of commerce, they have been able to go to the top. But it is very tragic that there is no educational medium so far as the Konkani-speaking population is concerned. I find from this Report that the contention of the Central Government, when its attention was drawn by the Kerala Government, was that there was no script for the Konkani-language. To an extent, it is true. But I find from the very same Report that in the State

of Maharashtra, the Government of Maharashtra have agreed to open Konkani schools if sufficient number of students forthcoming. The devanagari script has been recognised as the script for Konkani language by their All India Conference, etc. Therefore, the wishes of the people speaking Konkani where in the country should be responded to. In the same way, in Kerala there is what is known as the Tulu-speaking population. There is a notion so far as the border area of Kerala is concerned that it is a minority area. It is not. It is not a Tulu minority area. By and large, there are some Konkani-speaking people, some Kannada-speaking people also, but they have not got a script. But they have more or less accepted the devanagari script as the script for Tulu. To fulfil the aspirations of the Konkani-speaking population and the Tulu-speaking population in my State of Kerala and in various States wherever such population exists, should be fulfilled by giving them facilities for education in their own language.

Sir, one very disheartening thing in this Report is regarding the State of Tamil Nadu. It is wrong on the part of the Tamil Nadu Government if they think that Tamil Nadu is for Tamilians. I do not think that they think so, but if they think so, they would say they are wrong. The Government of Tamil Nadu for Tamilians are encouraged. I would appeal to the Government of India to see that this contention is encouraged in that State.

Going through this report I find that facilities for education in Hindi, Malayalam and Telugu have been going down every year. And even in the States under review facilities for education in these languages have gone down. Therefore, it should be seen through the process of negotiation and advice that the Government properly provides adequate facilities for the minority languages and minorities in that State.

One important suggestion that I find made in this report in regard to the Government of State services is that

[Shri K. Chandrasekharan]
ledge of the State official language should not be a pre-requisite for recruitment to State services and option of using English or Hindi as a medium of examination should be allowed. A test of proficiency in the State official language should be held during the period of probation. I think that this suggestion is a welcome suggestion and needs implementation. But I would only ask the honourable Minister how this is proposed to be implemented. A working knowledge of English so far as probably the South Indian States are concerned, and Hindi or the State language, and a fairly good knowledge for conversational purposes at least of the State language, should be ordinarily considered adequate for recruitment to the State services. Unless this portion of the report on this particular suggestion is implemented, I should think that we will be rather very far away from the position of really implementing the safeguards for linguistic minorities.

श्री सिकन्दर अली वज्ज (महाराष्ट्र) आली जनाब चेयरमैन, मैं जब यहाँ आनरेबल मेम्बर्स की तकरीरे सुन रहा था, तो दूसरी जबानों के बारे में और माइनरिटीज के साथ क्या सलूक रहा है, तो मुझे हिन्दुस्तान की एक बड़ी छटी जबान का खयाल आ रहा था, जिसका नाम उर्दू है और ये मारी जुबानों की जो शिकायतें हैं, वह सब शिकायतें मेरी उर्दू जबान की भी है। अभी हमारे त्यागी जी फरमा रहे थे कि ५० पी० में जो हो रहा है, वह इलेक्शन के सिलसिले में हो रहा है।

श्री महावीर त्यागी वह मैंने इसलिए कहा कि अब तक गफलत थी। इतनी जरूरी चीज की बिल्कुल लापरवाही की। अब उठे हैं इतने दिनों बाद। क्या उर्दू इतनी कम चीज थी? उर्दू वहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है।

श्री सिकन्दर अली वज्ज : जो आप उर्दू बोलते हैं, अगरचे हम शायर हैं, वह फिर भी हमारे लिए काबिले तकलीद है। हमको खुशी है कि हमारी पार्टी उर्दू की मदद के लिये तैयार हुई है और मदद के लिए आप भी उठे हैं। लेकिन मुझे तो

आज अपोजिशन से कम कहना है, मुझे अपनी पार्टी के लोगो से ज्यादा कहना है

“बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं जैसी अब है, तेरी महफिल कभी ऐसी तो नहीं।”

श्री महावीर त्यागी मुभान अल्ला, मुभान अल्ला

श्री सिकन्दर अली वज्ज : हमारे जो आनरेबल श्री मोहसिन इस रिपोर्ट के मिलसिले में आये हैं, वह उर्दू ज्यादा नहीं जानते। मैं नहीं जानता कि उर्दू उन्होंने कितनी पढ़ी है। इससे साबित होता है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है मुसलमान तो 6 करोड़ है, जिनमें सिर्फ दो-तीन करोड़ की जुबान उर्दू है। अब यह तो बात कहनी जरूरत नहीं रही, अब तो जनसंघ वाले श्री दूसरी जमाते भी कह रही हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमान की जुबान नहीं है। लेकिन वह यह बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं यह 6 करोड़ लोग उर्दू जुबान के लिये हक न भागने लगे। मैं तो सियासी आदम नहीं हूँ, शायर हूँ, पेशन शायरी की नहीं पाता हूँ, जज की पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे में उर्दू तरक्की करे। मेरी जुबान के साथ अब तक इसाफ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि त्यागी जी जैसे लोग उर्दू के लिये कुछ कहें। अब कांग्रेस में शरीक हुआ तो लोगों ने कहा कि आप अजन्ता पर नज़्म लिखने में बीस साल लगाये एलोरा लिखने पर दस साल लगाये, लेकिन अगर आप उर्दू के हक में या मुसलमानों के हक में कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप कम्युनिस्ट हैं। मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है लेकिन अगर मैं कम्युनिस्ट समझा जाऊँ तो शायद इस हाउस में कोई सेक्युलर नहीं होगा। मैं मुसलमान उर्दू को अपनी भाषा नहीं कहते हैं...

श्री महावीर त्यागी मेरा चेलेंज है कि इम्तहा हो जाय उर्दू में और फिर देखा जाये कि मुसलमान जीतते हैं कि हम जीतते हैं।

श्री सिकन्दर अली वज्ज : यही मेरा कहना कि हिन्दू जीतेंगे। मेरा हरगिज यह खयाल नहीं है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। उर्दू का तालिबान है। मैं उर्दू जुबान की तारीफ

को थोड़ा बहुत जानता हूँ। यह मेरा भन्नेक्ट है। मैं यह जानता हूँ कि उर्दू जवान को फैलाने में हिदुओं ने बहुत कट्टीब्यूट किया है। मैं यह भी समझता हूँ कि मुसलमानों का लेबल लगा कर के मुस्लिम लीग जैसी जमातों ने मियामी तौर पर और जवान के मामले में मुसलमानों को और उर्दू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

श्री महावीर त्यागो : यह भी गलत है। आप जा करके यू० पी० में देखें कि वहां हजारों मुसलमानों के बच्चों ने आजकल खुशी से हिन्दी सीखी है।

श्री उपसभापति : यही बात वे कह रहे हैं।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जहां लाखों करोड़ों उर्दू बोलने वाले हैं, वहां उर्दू को कल्ल किया गया। यू० पी० में आजादी के 25 साल बाद उर्दू वाले भी कहते हैं कि हम को उर्दू जवान न दी जाय, बल्कि हिन्दी दी जाये, क्योंकि अब उर्दू उनको रोटी नहीं दे सकती। दूसरी कल्ल-गाह आंध्र प्रदेश है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद वहां उसमानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू जवान हटा दी गई। क्या यही हमारा नेशनलिज्म है ? बिहार में भी यही हुआ। जहां तक महाराष्ट्र का मामला है, वहां उर्दू को हर किस्म की महलियत हासिल है और सिर्फ बम्बई शहर में जितने उर्दू के स्कूल हैं, उतने सारे हिन्दुस्तान में नहीं हैं। यह अलग बात है कि उर्दू वालों को वहां नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इसका सबूत उर्दू में मुखानिफत नहीं है। वहां तो उर्दू वाले मराठी भी जानते हैं। मैं गोरे साहब और गाडगील साहब, कुलकर्णी साहब से पूछना चाहता हूँ कि "महाराष्ट्र कोशाचा ?" यानी महाराष्ट्र किसका है; क्योंकि चव्हाण साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र बनने पर महाराष्ट्र उन्हीं का होगा जो उसकी खिदमत करेंगे। लेकिन बाल ठाकरे साहब कहते हैं कि जिनके माबाप की जवान मराठी नहीं है, उसका महाराष्ट्र नहीं है। कांग्रेस की वहां सरकार है, इसलिये वहां की सरकार को इस मामले का तसफिया करना चाहिये। हम कहते हैं कि हम मराठवाडा के वाशिदे जब पांच जिलों के साथ महाराष्ट्र में गये तब वह

महाराष्ट्र बना, वना वह नहीं बनता। अब मे भी दबी हुई चिंताएँ मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : विदर्भ वाले क्या

श्री सिकन्दर अली वज्द : मैं तो कह महाराष्ट्र की तस्मीम नहीं होनी चाहि के मामले में भी गवर्नमेन्ट ने यह तय है कि उसकी तस्मीम नहीं होगी। तस्मीम का नतीजा यह हुआ कि नौकरी पर हुए मुझे दस साल हो गये, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितनी पेण क्योंकि अभी तक इसका कोई तसफिया है। इसलिये मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे तस्मीम हो। जिनकी मादरी जवान उनका महाराष्ट्र है, ऐसा कह कर व जैसे लोग गलती करते हैं। कहीं ऐसा न महाराष्ट्र भी तस्मीम हो जाये। मेरे व कर्णी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे मेटेरियन हैं, बड़े माहिर हैं, बाल ठा कहते हैं कि जिनकी जवान मराठी है, उनका है। मैं श्री कुलकर्णी से पूछना कि आखिर महाराष्ट्र किसका होगा ? राष्ट्र से बहुत महबबत करता हूँ, मैं उ मत कर रहा हूँ और इसलिये मैं चा. गवर्नमेन्ट को इस बात को माफ कर दे नहीं तो लोगों के दिलों में शक पैदा एक नौजवान जो मुसलमान था और उसने उर्दू में एम० ए० किया था। जो हिंदी का हामी हो जाय तो उसकी ब होती है, और वह उर्दू में एम० ए० कहा कि उर्दू और हिंदी में फर्क को सिर्फ लिपि का फर्क है। बाबू जगजीव ने उसकी बहुत पीठ ठोकी और कहा बड़े मार्क की बात कही है। मैं चा. हमारे मिनिस्टर साहेबान जिस बात को उसके बारे में कोई बात न कहा करे। शते हैं कि यह सब हिंदी वाले हैं श्री मिटाना चाहते हैं। मिनिस्टर के मायने यह वह हर मन्त्रिज्म को जानना ही हो, लेकिन मिनिस्टर खड़े होते हैं तो माडर्न आर्ट पर एनर्जी पर और माइनारिटी लैंग्वेज पर

[श्री सिकन्दर अली वज्ज]

करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको अपने हृदय मालूम होने चाहिये। अब रही उर्दू की बात। उर्दू के शेर तो सब से ज्यादा अपोजिशन वाले ही पढ़ते हैं। बहुत से मजहबों की किताबें उर्दू में हैं। उसमें वेद है, उपनिषद् है, उसमें गीता का तर्जुमा है, धम्मपद है और कालिदास के कामों का तर्जुमा है और बाइबिल भी है यह सब उर्दू में है। बाज़ लोग कहते हैं, कि उर्दू में सिर्फ मुसलमानों का लिटरेचर है। इसमें शक नहीं कि उसमें मुसलमानों का लिटरेचर बहुत है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी बहुत सा लिटरेचर उर्दू में है। हमारे आर्य समाजी भाई चले गये, उनका सत्यार्थ प्रकाश भी उर्दू में है। उर्दू ने सब की खिदमत की है। उर्दू किसी एक फिरकें की जवान नहीं है। मगर एक बात है। किसी का कल छिपता नहीं, कल बोलता है। इसी लिये उर्दू के कातिल तीन सूबों, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार की मिनिस्ट्रिया आधी ओग उलट गयी। एक उर्दू शायर ने कहा है, त्यागी जी सुनिये।

“करीब है यार रोजे महशर,
छिपेगा कुशों का खून क्यों कर।

जो चुप रहेगी जवाने खजर,
लहूँ पृकारेगा आम्तों का” ॥

और अकबर डलाहाबादी ने कहा है :

उर्दू में जो सब शरीक होने के नहीं,
इस देश के काम ठीक होने के नहीं,
मुमकिन नहीं शेख इम्रान कैसे बने,
पंडित जी बाल्मीकि होने के नहीं ॥

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वाह-वाह में भी यह लोग शरीक नहीं होते।

(Interruption)

श्री सिकन्दर अली वज्ज यह उर्दू फक्त शायरी नहीं है। उर्दू में जो शरीक होते हैं। वह सिर्फ यू०पी० के नहीं होते हैं। वह उर्दू तो पूरे नेशन की जवान है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको पूरी एज्केशन को नेशनलाइज करना पड़ेगा, अगर आप मुल्क में इटी-ग्रेशन चाहते हैं। महाराष्ट्र में आज जैसी तारीख लिखी जा रही है उस पर मुझे एतराज है। उसमें देश को डिमिटीग्रेट करने का ज्यादा मसाला है। इसका डुरुस्त करना चाहिए। हमको इस तरीके से सोचना है कि हम हिन्दुस्तानी हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि

मैं उर्दू वाला हूँ और मारा हिन्दुस्तान मेरा है, परेशानी नहीं है कि उर्दू को कोई स्टेट नहीं मिल मुझे खुशी है कि सारा हिन्दुस्तान उर्दू का है। मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई आमासी है, कोई महाराष्ट्रीय है, तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ हिन्दुस्तानी कौन है और हम उर्दू वाले ही सब हिन्दुस्तानी हैं। मैं कोई शिकायत नहीं करता हूँ, न मुझे यह भी खुशी है कि अब उ के मिलमिल में सबकी आखें खुल गयी हैं। उ वाले इस मुल्क की खिदमत में किसी से पीछे नहीं है अभी चन्द रोज पहले मुझे उर्दू लिटरेचर की एडिट देखने का मौका मिला जिसमें हमारे शहर, हमारा नदिया, हमारे शायर, हमारे ऋषि-मुनि इस किस्म 10 वाल्युम उर्दू में तैयार हुए हैं। यह है उर्दू लिटरेचर जिस पर इस्लामी छाप होने का एतराज है।

श्री महावीर त्यागी : उर्दू आशिकों की और हिंसाशूकों की जवान है।

श्री सिकन्दर अली वज्ज इसी लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आशिकों के बारे में। एक बुजुर्ग ब्राह्मण बन्धनवा ने 5,000 साल पहले कहा था—

कुफर काफिर को भला शेख को इस्लाम भला
आशिका आप भले अपना दिलाराम भला

उर्दू मिजाज अमल में सूफियाना मिजाज है। हमारे शायरों में कट्टर मोलवियों के खिलाफ जितना कहा है उतना किसी जवान में नहीं कहा गया। च रोज पत्रों एक दोस्त ने कहा था कि जिनमें बन्दे माना नहीं गया वह देश का गद्दार है। तो यह ठीक है मुझे बन्दे मातरम् पर कोई एतराज नहीं है। इस भी ज्यादा आगे चीजे लिखी गई हैं। खुद “इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया है—

“खाके वतन का मुझ को हर जर्ग देवता है।”

वे कहते हैं कि वतन का हर जर्ग-जर्ग मुझे देवता नजर आता है। जब मैंने “अजन्ता-एलोरा” लिखा था बाज़ लोगों ने एतराज किया था। तो मैंने उनको जवाब दिया था :

किम मुहम्बत और अकीदत से नराश है मनुष्य।

कावाये अहले नब्रर है वज्ज बुतखाना तेरा ॥

इसलिए मैं यह भी कहता हूँ कि उर्दू को जो मुसलमान की जवान कहता है वह भी गद्दार है—जो मुसलमान

को ट्रेटर कहता है वह भी गद्दार है। जो कहता है कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा" हमारा कौमी गीत नहीं है वह भी गद्दार है और जो यह कहता है कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" भी कौमी गीत नहीं है, वह भी गद्दार है।

श्री जगदम्बो प्रसाद यादव . कहने वाले कहा गए।

श्री सिकन्दर अली वज्जद वह तो खुदा के पास गए। उसका हिमाब-किताब हो रहा होगा। लेकिन अभी उनकी आवाज गूँज रही है। देखना यह नहीं है कि किमने कहा। देखना यह है कि क्या कहा 'यह आवाज तो अभी तक गूँज रही है। जेलों में गूँजी, फाँसी के तश्तों पर गूँजी।

200 वर्ष पहले के हमारे एक शायर "मीर" ने कहा है :

मीर के दोनों मजहब को तुम पूछते क्या हों, उन्ने तों।
कश्का खेचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया ॥

इससे उर्दू का मिजाज और अन्दाज मालूम होता है। उर्दू के खिलाफ इन 25 बरसों में, दूसरी जवानों में बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन दूसरी जवानों के खिलाफ उर्दू में ऐसा कोई मैटीरियल नहीं। मैं यहाँ पर एक कायेमी की हैमियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उर्दू का आदमी होने की हैमियत से बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में उर्दू कौमी जुबान बन गई है तो क्या हुआ। वहाँ पंजाबियों की मेज्यागिरी है और अगर कल पंजाबी कौमी जुबान बन जाये तो क्या हम यहाँ पंजाबी को छोड़ देंगे ? भाई, इश्क और इल्म में तास्मुब नहीं चलता। जुबान का कोई मजहब नहीं होता। बाज वक्न वतन छूट जाता है मजहब छूट जाता है, लेकिन मादरी जुबान नहीं छूटती। इकबाल कहता है—

तुर्की भी शीरी, ताजी भी शीरी।
इरफे मोहब्बत तुर्की न ताजी ॥

यानी न अरबी मीठी है न तुर्की मीठी है, लेकिन मुहब्बत का हर लफ्ज मीठा है।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : मैं भी आपकी खिदमत में जरा अर्ज कर दूँ।

मर रख दिया हमने दरे जानाना स
काफिर है जो मिजदा करे बुनखाना स

श्री सिकन्दर अली वज्जद, जनाब, मैं जज रहा हूँ। मैं तकरीरे सुनना ही रहा हूँ एक किस्मा सुनाऊँ। एक बहुत अच्छे ए काफ़ी कानून का जानने थे, लेकिन एक कम बहम कर रहे थे तो मैंने उनका गोक दिा कि क्या आप कानून भूल गये। वह जब मैं आये तो उन्होंने कहा कि मैं कानून तो हूँ, लेकिन पाच सौ रुपया मिला था इसी उर करने का। तो मुझे हर किस्म की बात सुनने है, लेकिन यहाँ मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें मैं यहाँ माल दा माल में खामोश था, मतलब यह नहीं है कि मैं बोलना नहीं बात यह है कि आज उर्दू का मामल है, इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ। मुझे ब है। मैं कोई अपना कमाल दिखाने के र रहा हूँ। किसी ने कहा कि मैं कमिटिड हूँ और अभी एक म्शायरे में उन्होंने मुझ कायेम में गये तो आपकी शायरी का क्या मैंने कहा।

हर कली खून में नहाई है।
लोग समझे बहाग आई है ॥

और फिर अपने बारे में कहा

हमने लिख्वा ल् में अहदे व
हम पे इलजामे बेवफाई है ॥

तो जनाब में कमिटिड शायरी के इल कबूल कर सकता।

एक बहुत अहम बात अर्ज करन बाबू जगजीवन राम जी ने मैंने मुझे बड़ी खुशी हुई कि शकरकोट पाकिस्तान के खिलाफ मुमलमानों ने स किया। मुझे खुशी है कि मैं भी और मुझे इस पर फख है। मुझे अपने पर अफसोस नहीं है। मुझे फख भी है और किसी को मुस्लिम, क्रि

[श्री सिकन्दर अली वज्र]

होने पर शर्माने, पछताने और घबड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह मुल्क सब का है और हमारा कास्टीट्यूशन सब की हिफाजत करता है। मुझे तो इतना ही अर्ज करना है कि उर्दू का जो कानूनी हक है वह उसे मिलना चाहिये। हमारा आल इंडिया रेडियो जो है उसने भी जो भर कर उर्दू को कल्ल किया है और उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी जिस तरह हलाक किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं। न उसकी हिन्दी ममझ में आती है और न उर्दू समझ आती है।

जनाबवाला, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि कम से कम इस रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें हैं, उनको अमल में लाइये, मैं सब जवानों की हिमायत की बात करता हूं और उसके साथ यह भी अर्ज करता हूं कि कम से कम उस जवान का जरूर तो खयाल किया जाय, जिसको तीन करोड़ हिन्दु-स्तानी बोलते हैं। मुझे सेन्सस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। औरंगाबाद में मेरे घर के बीस आदमी रहते हैं, लेकिन वहां कोई सेन्सस का आदमी नहीं आया और उसने न मालूम क्या लिख लिया। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि पंजाब के जो आकड़े हैं, वह काबिले एतबार नहीं है—यह बिल्कुल ठीक है। मुझे तो हर लिखिस्टिक माइनारिटी के मिलमिले में इस रिपोर्ट की हर एक सिफारिश से इत्तिफाक है और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट जागी है। उर्दू के लिए यू० पी० में जो काम हो रहा है वह कल आंध्र में भी हो जायगा। किसी की जवान से हमको कोई झगड़ा नहीं है। जहां कहीं किसी जवान के साथ नाइन्माफी हो तो मैं उस जवान के लिये भी इसी तरह लड़ूंगा जिस तरह मैं अपनी जवान के लिये लड़ता हूं। ऐसे मामलों में हम साथ मिल कर चलेंगे।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज हम इस मदन में भाषाजात अल्पसंख्यकों के विषय में वाद-विवाद कर रहे हैं। श्रीमन्, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय हमारे यहां जो प्रान्त थे, प्रदेश थे, वह मल्टी-लिग्विस्टिक ज्यादा थे, इसलिए आजादी से पहले

भी और इसके बाद भी इस बात को महसूस किया गया कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के उभार के लिए यह आवश्यक है कि उसको अपनी भाषा में ही अपने को एक्सप्रेस करने और अपने को प्रकट करने का पूरा-पूरा मौका हो। स्टेट्स का डि-लिमिटेशन हुआ, नई स्टेट्स बनीं और इन बात की कोशिश की गई कि जहां तक हो सके एक-भाषायी प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन, श्रीमन्, एक-भाषायी प्रदेश भी बने, दो-भाषायी प्रदेश भी बने, राज्य बने, लेकिन इसके बावजूद जहां एक भाषा के भी प्रदेश बने वहां काफी सख्या ऐसे लोगों की रह गई जो उस भाषा को छोड़ कर एक अपनी दूसरी भाषा बोलने और पढ़ने हैं। यही वजह थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा-ज्ञान अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षाएं की और उन सुरक्षाओं को लागू करने वाले संस्थान अधिक मशकत बनाने की सिफारिश की। इसलिए हम देखते हैं कि कास्टीट्यूशन में जो आर्टिकल 29वां है, इसमें लिखा हुआ है :-

“(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.”

यह अधिकार हमारे संविधान के अन्तर्गत दिया हुआ है। इसी तरह से श्रीमन्, आर्टिकल 347 में लिखा हुआ है :-

“347. On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.”

मैं सब तो नहीं पढ़ता, लेकिन इसी तरीके से आर्टिकल 350 में यह अधिकार दिया गया है कि :-

“Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.”

इसी तरह से और भी दिया हुआ है। श्रीमन्, आर्टिकल 350 (ए) में इस बात की कोशिश की गई कि प्राइमरी स्टेज में लोकल बाडीज में जो प्राइमरी एजुकेशन हो, वह लोगों की अपनी मातृभाषा में हो। श्रीमन्, मातृभाषा के मानी यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद जिस भाषा को अपनी मा के दूध के साथ सीखता है, वह उसकी मातृभाषा मानी जाती है। लेकिन देखने में यह आया कि बावजूद इन कास्टीट्यूशनल प्रोटेक्सन्स के, इन कास्टीट्यूशनल सेफ़गार्ड्स के, हर स्टेज से इस बात की शिकायत आती है कि उनका पूरा-पूरा कार्यावित नहीं होता है। उनका पूरा-पूरा इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। महाराष्ट्र का जिस समय नया स्टेट बना, तब बहुत कुछ ऐसे भी हिस्से बहा गये हैं जो कि एक जमाने में कन्नड बोली जाने वाले क्षेत्र थे या कहिए किसी वक्त में मैसूर का हिस्सा था। अब वहां की शिकायत यह है कि वहां के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में पढ़ने की सुविधाएं नहीं हैं और मराठी भाषा उनके ऊपर जबर्दस्ती थोपी जाती है। यह एक बोन आफ कन्टेशन है, मैं उसमें तो जाना नहीं चाहता कि वह कहां तक सही है, कहा तक गलत है, मगर एक बात जरूर चाहता हूं, जब हमने कास्टीट्यूशन में ये सेफ़गार्ड्स किये और जैसा कि इस रिपोर्ट के अन्दर भी लिखा हुआ है कि अगर किसी स्कूल के अंदर 40 बच्चे हो या किसी जगह या किसी एक खाम कक्षा में 10 विद्यार्थी भी हो तो उनको उनकी मातृभाषा में एक टीचर रख कर पढ़ाने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी भाषा में देने का अधिकार होगा और यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी जिले में 15 या 20 परसेंट आदमी एक अमुक भाषा को जानने वाले हो तो उस जिले के अंदर जो सरकारी नोटिस और प्रकाशन होंगे, वे उस भाषा में भी किये जायेंगे, वहां की स्टेट भाषा के साथ-साथ। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि राज्य मुख्यालय में एक ट्रान्सलेशन ब्यूरो होगा जो विभिन्न भाषाओं के अंदर ट्रान्सलेशन किया करेगा और यह भी है कि जिस भाषा में याचिका या पेटिशन या आवेदन-पत्र होगा, कोशिश यह की जाएगी कि उसी भाषा में उसको उत्तर दिया जाये। एक यह भी मिफारिश थी कि राज सेवाओं में भर्ती के लिए, राज्य की सरकारी भाषा के पूर्व-ज्ञान की शर्त नहीं होनी चाहिये और परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग

करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सब श्रीमन्, भाषाओं के बारे में कहा गया है।

जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में वहां की इस तरह की शिकायत है कि उनको अपनी सीखने की सुविधा नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी शिकायत है।

अब मैं पंजाब की बात कहना चाहता हूँ रिपोर्ट के पेज 60 में लिखा है कि पंजाब सरकार प्रश्नावली भेजी गई थी, उसके सबब में वहां की ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी प्रकार आकड़े ही दिये कि वहां पर लिग्विस्टिक मा कितनी है या नहीं है। अगर वहां पर लि माइनारटीज हैं तो उनका परसेंटेज कितना तरह के आकड़े वहां की सरकार ने नहीं दिये, यही नहीं, चर्चा के दौरान भी इस ओर कमीशन का ध्यान दिलाया गया, परन्तु सरकार का कहना है कि हमारे यहां तो अल्प सङ्ख्यक नहीं हैं। मगर कमीशन का कहना कि यह तथ्य सही नहीं है।

यही नहीं, श्रीमन्, जो मन्चर फार्मूला था भी उन्होंने रद्द कर दिया। वहां के लोगों ने 347 और 350 के अन्तर्गत यही मांग की है कि पंजाब सरकार को यह निर्देश दे कि स मुताबिक भाषा अल्प सङ्ख्यकों को हिन्दी उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय।

श्रीमन्, इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं। लोगों को कहीं कुछ सुविधा प्रदान की भी नहीं हिन्दी के बारे में तो सरकार से जो सुविधाएं प्राप्त थी, उन्हें भी बन्द कर दिया है। उस मालूम पड़ता है कि पंजाब सरकार ने हिन्दी में आफेंसिव ने रखा है या ऐसा कदम उठाना है। हिन्दी भाषियों के प्रतिनिधियों द्वारा है कि पंजाबी विश्वविद्यालय की पाठ्यपुस्तकें के विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक तथा उच्चतर स्तर पर माध्यम के रूप में हिन्दी ली हो, हिन्दी माध्यम नहीं ले सकते, जबकि अंग्रेजी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बात रिपोर्ट में है। इस तरह हिन्दी के साथ वहां पर भेदभाव

[श्री नवल किशोर]

रहा है। मैं यह देख रहा हूँ कि वहाँ पर पहले उर्दू के साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता रहा लेकिन हिन्दी के साथ खास तौर पर भेदभाव किया जाता है। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा, जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज है कि हिन्दी तथा उर्दू भाषियों को प्राथमिक तथा माध्यमिक सरकारी स्कूलों में अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की वांछी मुविधाएँ नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पंजाब सरकार क्यों वांछी गारन्टी नहीं दे सकती है ?

इसी तरह से इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मार्च, 1971 में चंडीगढ़ वार्ता के दौरान शिक्षा सचिव द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि पंजाब सरकार का शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में केवल पंजाबी को ही शिक्षा का माध्यम रखने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। पंजाब सूबा भी हिन्दुस्तान का एक सूबा है और मैं पंजाबी भाषियों की इज्जत करता हूँ। मुझे इस बात का दुःख है कि इस बारे में उनका इस तरह का एटीट्यूड क्यों है ? सविधान में इस बात की गारन्टी है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस बात की अवश्य कांशिश की गई है कि हिन्दी भाषा का किसी व उपर शोषण न जाय, बल्कि आदिम-आदिम उत्तर दक्षिण एवं और पश्चिम में वह स्वयं उभर कर आए और अन्त में वह सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाये। एक तरफ तो हमारे सविधान में इस तरह की बात कही गई है और दूसरी तरफ पंजाब में हिन्दी व खिलाफ इस तरह का विरोध है जो कि वांछित वर्द्धाण नहीं है।

इसी तरह में आप दबंगे कि तमिल नाडु की जहाँ तक बात है, तमिल नाडु में जा तमिल भाषा है वह अपनी जगह पर है और भी जितनी रिजनल भाषाएँ हैं उनकी अपनी जगह है, सरकार इस बात की कायल है कि जो तीन सूचीय लैंग्वेज फामिला है उसकी लागू किया जाय मारे हिन्दुस्तान में। जब मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री था तो उस समय उत्तर प्रदेश में तीन सूचीय लैंग्वेज फार्मूला लागू करने की बात की गई थी। एक भाषा तो हिन्दी थी, दूसरी अंग्रेजी थी और तीसरी भाषा चाहे उर्दू हो या फिर माउथ इंडिया की कोई भाषा हो, जिसका

वहाँ पर विद्यार्थियों का पढ़ना चाहिए था जिसमें हर मनुष्य को कम से कम एक दक्षिणी भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे यहाँ लखनऊ के अन्दर ए इन्स्टीट्यूट खोल रखा है, जहाँ पर माउथ इंडिया भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर लोग माउथ इंडिया की भाषाओं को सीखते हैं तथा उसमें इम्तिहान पास करते हैं। मद्रास में हिन्दी के खिलाफ किसी तरह का आन्दोलन हो यह बात समझ में नहीं आती है जबकि मद्रास में भी काफी लोग हिन्दी बोलते हैं। इसी तरह आन्ध्र की बात है और पंजाब की बात है। हिन्दी क्षेत्रीय भाषाओं से टकराव कहा है ?

मेरे दोस्त जो अभी बोल रहे थे उनमें से मैं इस बात में इतिफाक करता हूँ कि उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं है। भाषा का कोई वास्ता किसी मजहब से नहीं होता। अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा होती तो आज बंगला देश के अन्दर वहाँ की भाषा बंगाली नहीं होती, उर्दू होती। आन्ध्र का हिन्दु आंध्र का मुसलमान दोनों तेलगु बोलते हैं। इसी तरह बंगला देश में और पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोलते हैं, तमिल नाडु में तमिल बोलते हैं। पाकिस्तान के अन्ध्र प्रदेश में मन्थी भाषा है, पंजाब में पंजाबी और उर्दू है। भाषा का कोई वास्ता मजहब से है इस बात में मैं नहीं मानता हूँ। मेरे दोस्त इतिफाक करेंगे कि हिन्दी के जो बड़े-बड़े कवि हुए हैं, जैसे कबीर हुए, रही साहिब हुए, रसखान हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य खजाने का अपने योग्यता से भर दिया वे हिन्दी नहीं थे। चक्रवर्त्त मुसलमान नहीं हैं, फिराक साह मुसलमान नहीं हैं, मुल्ला साहब जो इस वक़्त यहाँ न हैं और उर्दू के एक अच्छे शायर हैं वे भी मुसलमान नहीं हैं। जहाँ तक उर्दू का वास्ता है, मैं उन लोगों से हूँ जो उर्दू को उत्तर प्रदेश की अपनी भाषा मानते हैं जितनी हिन्दी को मानते हैं। झगड़ा स्ट्रिट का पड़ना है कि कोनसी स्ट्रिट हो। मैं जा जवान बोलता हूँ वह न ठेठ हिन्दी है ठेठ फारसी है वह ऐसी भाषा है जिसका सब समझते हैं . . .

श्री सिकन्दर अली बज्द : आप उर्दू बोल रहे हैं

श्री नवल किशोर : इसको मैं उर्दू कहता हूँ, हिन्दी कहता हूँ हिन्दुस्तानी कहता हूँ। एक चीज जो मुझमें लगती है वह यह है कि भाषा को उसकी मैरिट पर

हमको डिस्कम करना चाहिये। उत्तर प्रदेश में इस बात की कोशिश की गई और इस बात के आदेश हैं गवर्नमेंट के कि कचहरिया में जो भी चाहे उर्दू में एप्लीकेशन दे सकता है, वहां ट्रांसनेशन का भी इन्तजाम है। यह भी है कि जिन कक्षा में पांच विद्यार्थी भी उर्दू चाहेंगे, वहां टीचर को मुहैया करना पड़ेगा। दिक्कत यह पत्नी है—मेरा एक्मपीग्रिम भी है—कि हमने टीचर दे दिया, लेकिन वहां पांच स्टूडेंट भी नहीं मिलते। मगर, श्रीमान, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उर्दू भी उत्तर प्रदेश के अन्दर पोलिटिकल बन गई है। मैं 100 परसेंट अपने उन दाम्नों के साथ हूँ जो उर्दू की तरफकी चाहते हैं। उर्दू भी हमारी 11 भाषाओं में से है। उर्दू, जैसा व्यापी जी न कहा, आशिकों की भाषा है और हिन्दी मातृका की भाषा है। अगर आपन इस बात को एक्सेप्ट किया ता आशिक का भी मातृका की भाषा पढ़नी पड़ेगी, यह नहीं कि सिर्फ मातृका ही आशिक की भाषा पढ़े, क्योंकि वायदा यह है कि आशिक का दखना पढ़ना है मातृका से।

श्री पीताम्बर दास : उत्पत्ति का तब मजा है जा दोना हा बेकगर।

श्री नवल किशोर : और दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उर्दू की सही प्रिदमन तभी करेंगे

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीम मेहता) : हम करेंगे।

श्री नवल किशोर श्रीम मेहता आपकी गिनती मातृका में होती है, आप मन बोला।

श्री महावीर त्यागी काश्मीर के रहने वाले सब मातृका हैं।

श्री नवल किशोर : ता मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर आप उर्दू की तरफकी चाहते हैं ता आपका यह भी कहना पड़ेगा कि हमारा उद्द परम्पन साथी उर्दू के साथ-साथ हिन्दी को भी पढ़े। हम लोग उर्दू पढ़े, वे लोग हिन्दी पढ़ें। यह सबाल हिन्दू-मुसलमानों का नहीं है। होता क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ता आजकल बड़ा जोर है उर्दू के टीचर्स नियुक्त करने का।

हमारी गवर्नमेंट की बात आप यह मकने है चाहे गलती की हो। लेकिन इस पार्टी कल तक थी, फिर प्रेसिडेंट शासन भी। मगर अब पता चला है कि दो हजार उर्दू विद्यार्थी हैं और इतने ही और किये जायेंगे लिये या उसकी तरफकी के लिये उनका न सिर्फ दो हजार वर्कर्स पैदा किये जा रहे हैं के आन वाले चुनाव के लिए।

श्री श्रीम मेहता : यह बात नहीं है

श्री नवल किशोर : श्रीम मेहता, आप भी हैं कमिनि भी हैं, लेकिन जो चीज मैं उसका भी ध्यान से सुनो।

आप ताज्जब करेंगे। उर्दू एडिटरस व हुई। उसका स्वागत करना है। जो उद्योग जायेंगे उर्दू की तरफकी के लिए साथ दगा। मगर वह उर्दू एडिटरस काफेस की तरफ में नहीं थी, वह एक स्ट्रेज मैनेज्ड

श्री सिकन्दर अली बज्ज : हिन्दू राष्ट्र भी उसके बारे में क्या था?

श्री नवल किशोर : हा मरना है व, मैनेज्ड था हा। इस समय मैं हिन्दी अकपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। उसमें शेख तशरीफ ले गये थे और प्रधान मंत्री भी मैं कि आप उनके पत्र में न पढ़ें।

श्री सिकन्दर अली बज्ज : 60 वर्ष के पत्र में नहीं आता।

श्री नवल किशोर : मैं यह बात समझ आदमी की इंटेलिजेस कभी स्टेटिग नहीं हो डायनेमिक है। मरी इफार्मेशन यह है कि देशन इस काफेस में डाटर्कटर आफ इ इश्यू किये। 1 लाख 14 हजार रुपये गवर्नमें में दिये गये। इसमें उर्दू की सही मेवा न लाग जरूर बहकाये जा सकते हैं। मर काई भी गवर्नमेंट हा उत्तर भारत में हा या दार् में, मैं इस बात का मानता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जो भाषा है, चाहे वह भाषा हिन्दी हो हा या और भाषा हा, उसकी न विज्ञानी ही

[श्री नवल किशोर]

मैं न पशियनाइज्ड उर्दू के हक में हूँ, न संस्कृटाइज्ड हिन्दी के पक्ष में। इसी लिए गांधी जी ने कहा था कि हमको उर्दू और हिन्दी मिली जुली हिन्दुस्तानी भाषा पर फ़ख़ होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि बाबू जगजीवन राम ने बिहार में क्या बात कही मगर एक बात मैं जानता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, हर स्टेट की जो अपनी भाषा है, उस भाषा के साथ साथ मैं इस विचार का हूँ कि हिन्दुस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें अल्पसंख्यकों की जो भाषायें हैं, उनका सुधार होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसा चमन है जिसमें अगर तरह-तरह के फूल नहीं खिलेंगे तो उसमें एक मोनोटनी पैदा हो जायेगी।

आज भाषा के नाम पर फ़ैनेटिज्म चाह हिन्दी के समर्थकों का हाँ, चाँड़ ऐंटी हिन्दी के समर्थकों का हो, मैं उन लोगों से हूँ जो हिन्दी को किसी स्टेट पर थोपना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह बात आपको माननी पड़ेगी कि यदि हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र की शक्ल में एकता के साथ रहना है, तो कोई न कोई भाषा इसकी होगी। चाहे तमिल राष्ट्रभाषा बन गई होती, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, मगर अंग्रेज़ों का पसन्द करे, हिन्दी से हम नफ़रत करे, श्रीमन्, यह हमारी देश-भक्ति, पैट्रियाटिज्म के खिलाफ़ है। बंगला भाषा बहुत स्वीट है जैसे कि यूरोप में फ्रेंच कही जाती है वड़ी स्वीट भाषा है। अगर मुह में रमगुल्ला रख कर हिन्दी बोलिये तो वह बंगला हो जाती है, मुह में ककड़ भर कर बोलिये तो दूसरी भाषा हो जाती है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो जो इनकी मीठी भाषा है कि बिना रमगुल्ले के मिठास आ जाए तो मैं रम व्यू का हूँ कि ऐसी भाषा सबको मीखनी चाहिए। मैंने जेल में गुजराती पढ़ी।

मैं जो बात कहना चाहता था इस कमिशन की रिपोर्ट के बारे में वह यह है कि इस कमिशन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में यह बात बताई है कि बावजूद कस्टीट्यूशनल सेफ़गार्ड के बावजूद सरकारी कमिटेय के बावजूद हमारी लम्बी-लम्बी स्पीचिंग के, आज भी हर स्टेट के अन्दर जहाँ लिग्विस्टिक माइनारिटीज हैं, उनके साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझे पंजाब की क्या स्थिति है, इसका पहले इतना ज्ञान नहीं था। अभी तक मैं समझता था कि साउथ में ही अपोजिशन है। मगर हरियाणा और पंजाब जो कल तक एक था, वहाँ जिन लोगों को प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त थी, वह भी अब बन्द कर दी गई है। अगर हिन्दुस्तान में यह चीज़ चलेगी, इस समय वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, मगर मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मगर जिम पार्टी की सरकार यहाँ है उसी को वहाँ की गवर्नमेंट हो, तब फिर यह कितने शर्म की बात है कि पंजाब के अन्दर हिन्दी के साथ यह बर्ताव किया जाए और वहाँ की गवर्नमेंट कह दे कि कोई लिग्विस्टिक माइनारिटीज वहाँ नहीं है। ऐसे फ़ैनेटिक स्टेटमेंट को हम कैसे बर्दाश्त कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ।

श्री महावीर त्यागी : लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पंजाब में जिम पार्टी की गवर्नमेंट है, उसी पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है, तो क्या यह इसको ठीक नहीं कर सकते।

श्री नवल किशोर : इसी लिए और भी जरूरी है गया हमारे मोहम्मिन साहब बैठे हैं, पता नहीं यह कितना कर पायेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पंजाब सरकार को बुला करके कहें कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का आप क जो ऐंटिड्यूड है, वह बिलकुल गलत है और काबिज़ बर्दाश्त नहीं है, उसको चेज कीजिये, अगर वे चेज नहीं करते हैं तो अडर आर्टिकल 347 और अडर आर्टिकल 350 उसको प्रेमिडेट साहब की तरफ से डाइरेक्ट दिया जा सकता है। इसी तरह से चाहे आंध्र की स्टेट हो, चाहे तमिल नाडु की स्टेट हो, चाहे उड़ीसा की स्टेट हो, चाहे कोई और स्टेट हो, कहीं इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। मैं यह चाहूँगा कि उर्दू भाषा में उत्तरी भारत की भाषा न हो ऐज वन आफ दि इलेग्जेंस। इसका अगर विकास दक्षिण में भी हो, मुझे इस बात की खुशी होगी। (Interruption) अपने भाई से कहूँगा कि आप तमिल नाडु में जाकर उर्दू बोलिये, तो लोग पूछेंगे कि किस देश से आये है

श्री सिकन्दर अली बज्ज : मैं मद्रास में मुशायरे गया तो वहाँ दस हजार आदमी शरीक हुए और नी

दिन मुशायरा चला। वहाँ हम जवान को लोग समझते हैं।

श्री नवल किशोर : आप मुशायरे में गये थे। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा मुशायरे से हट कर के आम लोगों में आ जाए।

श्री सिकन्दर अली वज्र : मुशायरे में पार्लियामेंट के मेम्बर कम आते हैं, आम आदमी ज्यादा आते हैं।

श्री नवल किशोर : मुझे भी बड़ा शोक है मुशायरे का...

श्री ओम् मेहता : आप भी कोई शेर सुना दीजिये।

श्री नवल किशोर : मैं इसको मुशायरा नहीं बनाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी रिपोर्टों के मबध में आज यह ट्रेड होता जा रहा है कि चाहे वह युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह लिग्विस्टिक माइनारिटीज कमिशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट हो, वह पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। उस पर बहस हो गई और हमारे पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ओम् मेहता साहब ने समझ लिया कि हमारा काम खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसी रिपोर्ट्स में जो सिफारिशें की जाये, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। ओम् मेहता साहब नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद साहब बैठे हुये हैं। उनका भी इससे बहुत बड़ा वास्ता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज भी सेंटर में हिन्दी के साथ डिस्ट्रिक्मिनेशन होता है। आपने कास्टिट्यूशनल कमिट्टीमेंट किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उसकी तरफ मजबूती के साथ आपको कदम बढ़ाना चाहिये। मैं इससे इतिफाक करता हूँ कि आप कोई काम ऐसा मत करिये जिस से किसी के जज्बात को ठेस लगे। मगर जब हिन्दी को आप को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो इस कदम को सेंटर से आप को शुरू करना पड़ेगा। सेंटर में चाहे ट्रांस्लेशन का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, आप हिन्दी के साथ डिस्ट्रिक्मिनेशन करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो सिफारिशें की जाय उनको इम्प्लीमेंट किया जाय। खास तौर से जो आसाम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदि की

वात कही गई है, लिग्विस्टिक माइनारिटीज के सबध में, उन पर विचार कर के वहाँ के लोगों को प्राप्तर प्रोटेक्शन प्राप्त होना चाहिए।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) : उपाध्यक्ष जी, भाषा, भाषा-भाषी उन के बहुमन और उनके अल्पमत पर जो विवरण आया है उस पर विचार हो रहा है। मुझे पहले तो भाषा के सबध में यह बात कहनी है कि भाषा की परिभाषा में वे ही भाषाये आती है कि जिनका अपना साहित्य होता है स्वतन्त्र रूप से और जिनकी प्रतिष्ठा किसी एक भू-भाग में होती है। भाषा का इतिहास यह कहता है कि दुनिया के प्रत्येक भू-भाग में जब कि वे एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे जितने कि आज हो गये हैं या विज्ञान ने जितना पास आजा उन को कर दिया है, उस समय अपने-अपने भू-भाग में अपनी अपनी भाषा की उत्पत्ति हुई। किसी भाषा का सिद्धान्त ध्वनि या तो किसी भाषा का सिद्धान्त कुछ और या और इस तरह से विभिन्न भाषाये बन गयी। हमारा अपना यह विशाल देश है और इसलिए स्वाभाविकतः बड़े देशों में कठिनाइयां होती हैं और इस कारण न जाने कितनी भाषाये इस देश में हो गयी, उन की उत्पत्ति इस देश के विभिन्न भागों में होनी थी और आप चाहे किसी भी बड़े देश को ले लीजिए, जैसे अभी योरोप का जिक्र हो रहा था कि वहाँ किन्तनी ही अलग-अलग भाषाये हैं और वे अपने-अपने किस्म से बनी इसी तरह में हमारे यहाँ भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और मध्य में अलग-अलग भाषाये बन गयी जो कि उनकी उत्पत्ति माना जाता है कि एक तमिल को छोड़ कर प्राकृत से या संस्कृत से या अपभ्रंश से हुई। यही कारण है कि तमिल को छोड़कर बाकी सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द पाये जाते हैं, किसी में अधिक और किसी में कम पाये जाते हैं। जब कि भाषावार प्रान्तों की रचना हुई तब उस समय सिद्धान्त तो यही था कि जहाँ एक भाषा बोलने वाले अधिक भाषा भाषी लोग हैं, उनका अपना भू-भाग है उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिले और वह अपने यहाँ के विद्या-थियों को अपने यहाँ के नागरिकों को उसी भाषा में शिक्षा दे सकें जो कि उनकी मातृ भाषा है या जिस भाषा को वहाँ का बहुमत बोलता है और यही कारण है कि एक बार प्रान्तों की रचना हुई, फिर कुछ एतराज हुए और फिर से उस सब पर विचार किया गया और

[पंडित भवानी प्रसाद तिवारी]

उमके बाद फिर कुछ प्रदेश और बन गये। अभी तक थोड़ा बहुत उमी का आधार ले कर राज्य बनने जा रहे हैं। हमारे अपने संविधान में ११ भाषाओं को अधिकृत रूप से माना गया। यह माना गया कि यह देश की प्रमुख भाषाएँ हैं। अभी विवाद में ऐसी भाषाओं का नाम दिया गया जैसे कि काकण ह, या टुलु ह, लेकिन भाषा की परिभाषा के अनुसार उन्हें भाषा नहीं माना जा सकता। उन को बाली कहेंगे, या टाग्लिट कहेंगे, पर पूरी भाषा, जिसमें साहित्य होता है वह उन को नहीं मान सकते। इस रिपोर्ट में जो प्रसंग है वह संविधान में बोलने वाली भाषाओं और उन के प्रसंग में अल्पमत और बहुमत जहाँ तहाँ पैदा होता है उस पर कुछ कहा गया है। अब आप देखेंगे कि देश में जो सब से अधिक भाषा बोली जाती है वह हिन्दी है। किसी प्रान्त में वह कम बोली जाती है, जैसे दक्षिण में, वहाँ यह अल्पमत में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में यह अल्पमत में है। उमी प्रकार सभी भाषाओं का हाल है। जैसे अभी आसाम का जिक्र किया जा रहा था कि आसाम में जहाँ असमिया बोलने वालों का बहुमत है, वहाँ पर दगाली जो है, कछार में जो लोग रहते हैं बंगाली भाषा भाषी है वह अल्पमत में है। इसी प्रकार पंजाब का जिक्र त्यागी जी ने किया और बताया कि वहाँ पंजाबी बोलने वालों का बहुमत है। आज जैसा पंजाब बन गया है उसमें यह ठीक है परन्तु वहाँ अल्पमत की भाषाएँ हैं उससे कोई टकार नहीं कर सकता और बोट टकार करना है तो चलन करता है। तो जो एक जगह बहुमत की भाषा है वह दूसरी जगह अल्पमत की भाषा बनती है। श्रीमन्, राज्यों का विभाजन हुआ है भाषाओं के अनुसार और तीन भाषाय हैं

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीम् मेहता साहब, अभी बोटिंग हो तो बराबर हो जायेगा।

श्री श्रीम मेहता : आप हमें हर दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : आप अलग से मैं पार्लियामेंट चलाओ यादव जी।

श्रीमन्, मैं अर्ज यह कर रहा था कि संविधान में जिन चौदह भाषाओं का प्रसंग आता है उनमें तीन

भाषाएँ ऐसी हैं जो कि किसी राज्य की बहुमत की भाषा नहीं जावे ऐसी स्थिति नहीं आई है और वे तीन भाषाएँ हैं—सिंधी, संस्कृत, और उर्दू। सिंधी—जिसका कोई राज्य नहीं है जहाँ कि वह बहुमत की भाषा नहीं जा सके, स्वयं संस्कृत जो है उसका बहुमत में बोलने वाला कोई राज्य नहीं है और उर्दू भी ऐसी ही भाषा है कि जिसका किसी राज्य में बहुमत नहीं है बोलने वालों का।

श्री एफ० एच० मोहम्मिन : काश्मीर में तो आप-जिनका जैगुज है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : काश्मीर में है। मैं करना यह चाहता था कि उमी उर्दू भाषा में—आज जिसकी चर्चा है अभी जो शायद साहब थे वह चले गये जिनमें उनमें सबध में बातें कही—उमी में भाषाओं के मध्य में इतनी ध्यारी और मीठी बात कही गई है जो सब पर लागू होती है—और अभी भाई त्यागी जी और सब लोग जिक्र कर रहे थे—तो उर्दू में ही एक इतनी मीठी बात कही है सब जवानों के बारे में। अभी आशिक साणूक वगैरह का भी चर्चा हुआ। कहा है कि एक की दाम्पत्य है प्यारे और अपनी अपनी जवान है प्यारे—यानी सभी भाषाएँ मानवधर्म का गुणगान गाती हैं, उनकी अपनी-अपनी स्टाइल है, अपनी-अपनी शैली है, अपनी-अपनी अभिव्यक्ति है, जिसमें वह अपने को अभिव्यक्त करने है। इसी तरह सभी जवानों का सामना है तो यह हमारी समझ में नहीं आता कि इसका राजसत्ता और उसके अधिकारों में जोड़ कर और जगह जगह अल्पमत और बहुमत के नाम में जो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत पैदा हो जाती है वह क्यों ! यह बड़ी गलत बात है। असल में समस्त भाषाओं का जो सबध है वह बड़ी और छोटी बहनों का सबध है। बहनों पर जहाँ बहुमत है बोलने वालों का वह बड़ी बहन है और जहाँ अल्पमत भाषा भाषी है वे छोटी बहन हैं और जो बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में सबध होता है यही सबध यदि सब जगह रह जाये—जैसे तामिल है—वहाँ नफरत न हो और वह समझे कि वह बड़ी बहन है और यहाँ जो अल्पमत है भाषा भाषियों का वह छोटी बहन है तो यह झट्ट खत्म हो जाये। इसी तरह से आसाम में या सब जगह यही उसका हाल है कि बड़ी बहन और छोटी बहन के रिश्ते से ये सब भाषाएँ आपस में रहे

मरकार इस संबंध में क्या करे। तो मुझे यह सुझाव देना है कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसा केन्द्र हो चाहे उसका आधा खर्चा राज्य वहन करे और आधा केन्द्र वहन करे जिसमें मिर्फ, नेगुजेज ही पढ़ाई जाय और चार भाषाएँ प्रत्येक सटर् में हो, ऐसे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ऐसे चार भाषा भाषी केन्द्र खोले जाय जिसमें केवल भाषाएँ पढ़ाई जाय। आप देखेंगे, और मेरी कल्पना यह है, कि जैसे मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ आम-आम मगटी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, तेलुगु या उडिया भी बोली जाती है, तो ये 4 भाषाएँ मध्य प्रदेश में पढ़ाई जाएँ, कहीं एक केन्द्र बना कर, इस तरह से प्रत्येक केन्द्र में करीब चार-चार भाषाओं के क्षेत्र हो, तो आपस में प्रेम होगा, नफरत नहीं होगी, फैलाव होगा, एक दूसरे की भाषा को लोण जानेगे। यह सुझाव मुझे देना है। दुनिया जिस तरह से चल रही है, हम अल्पमत और बहुमत के नाम को लेकर आपस में झगड़ते हैं, मार-काट करते हैं—यह हमारे लिए शर्म की बात है। दगला भाषा इतनी अच्छी भाषा है और उसकी अभिव्यक्ति इतनी शक्तिशाली हुई कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर मारी दुनिया को एक महाकवि

स्वीकार हुए और उनके बोलों के ऊपर आज इक्लाव होने हैं और जिसका कि हम अपने देश में माहानागिटी या अल्पमत की भाषा कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति इतनी ताकतवर हुई। आज रवीन्द्र नाथ ठाकुर कहलाते हैं, मारी दुनिया उनको ऐसा मानती है। आज मानस चतुष्कली में तुलसीदास के रामचरितमानस का रूसी में, अंग्रेजी में, अनुवाद हो चुका है और दुनिया उसको जान रही है। तो हम भी यही समझते हैं, समार ऐसा प्रयत्न करे कि प्रेमपूर्वक एक भाषा दूसरी भाषा में गले मिले और इस काम को आगे बढ़ाएँ, जिसका कि सकेत इस विवरण में है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 28th November, 1973.